बकाया भुगतान के लिए महाराष्ट्र में गन्ना किसानों ने उठाई आवाज

जयश्री भोसले | पुणे |

महाराष्ट्र सरकार और गन्ना किसानों के संगठनों ने चीनी मिलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वे किसानों का बकाया चुकाएं। राज्य सरकार ने मिलों से गन्ना किसानों के बकाया को 15 पर्सेंट की ब्याज दर पर गणना करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र शुगर कमिश्नरेट ने शुगर मिलों से कहा है कि वे किसानों का बकाया 15 पर्सेंट की ब्याज दर के साथ वापस करें। मिलों पर गन्ना किसानों के ₹1768 करोड़ बकाया हैं। मौजूदा सीजन में मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया ₹20,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है। वहीं केंद्र सरकार ने शुगर की एक्स-मिल फ्लोर कीमत को ₹29 प्रति किलो तय कर दिया है, जिसके बाद किसानों और उनके संगठनों ने मिलों पर बकाया लौटाने को लेकर दबाव डालना शुरू कर दिया है।

- 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे 2018-19 के पेराई सत्र के लिए गन्ने का रकबा 25% बढ़ने की संभावना

इस पर स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने कहा, 'बकाया बढ़ने के बावजूद हम लोग चीनी के दाम कम होने के चलते चुप रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार के शुगर इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज के ऐलान के बाद चीनी की कीमत ₹29 प्रति किलो के नीचे नहीं जा सकती। इसी वजह से हमने गन्ने के बकाया को लेकर 29 जून को राज्य के कमिश्नरेट पर मोर्चा खोलने का निर्णय किया है।' शेट्टी ने कहा कि अगर गन्ना किसानों को अभी उनका बकाया नहीं मिलता है तो वे 30 जून तक फसल पर लिया गया कर्ज लौटा नहीं पाएंगे। अगर किसान 30 जून तक इसे लौटा नहीं पाते हैं तो वे केंद्र और राज्य सरकार की इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

महाराष्ट्र में बढ़ा गन्ने का रकबा, ज्यादा चीनी उत्पादन की उम्मीद

देश के दूसरे सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे 2018-19 के पेराई सत्र के लिए गन्ने का रकबा 25 पर्सेंट बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि दूसरी फसलों के मुकाबले गन्ने से बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद और अच्छी जल उपलब्धता के कारण किसान गन्ने की खेती का रुख कर रहे हैं। वहीं, देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में भी बंपर पैदावार होने की उम्मीद है। हालांकि, यहां की शुगर इंडस्ट्री ने पहले ही प्रदेश सरकार बता दिया है कि वह अगले पेराई सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएगी। महाराष्ट्र शुगर कमिश्नरेट के सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में 2018-19 में गन्ने का रकबा 11.26 लाख हेक्टेयर रह सकता है, जबकि 2017-18 में यह आंकड़ा 9.02 लाख हेक्टेयर पर था। कमिश्नरेट जल्द ही रकबे से जुड़े आधिकारिक आंकड़े पेश करेगा।

ET
25/6/18